Constitutional bodies

Parameters	Election commission of India	UPSC	SPSC	JSPSC	Finance commission	National commission for SC/ST/BC	Special officer for linguistic minorities	CAG	Attorney/ Advocate general
Articles	324	315 – 323	315 – 323	315(Although mentioned in constitution it is a statutory body.	280	338/338A/ 338B	350B (7th CAA)	148 - 151	76/165
Composition	CEC + Other Election commissioners + President can appoint regional commissioner	Chairman + Other members as determined by the President	Chairman + Other members as determined by the Governor	Similar to UPSC	Chairman + 4 other members	Chairman + Vice chairman+ 3 members	Single member	Single member	Single member
Appointment	President. Also determines size of EC.	President	Governor	President	President	President by warrant under his hand and seal	President	President by warrant under his hand and seal	President/ Governor
Qualifications	Not prescribed	Half of the members should have experience under the govt of India or state govt for 10 years.	Half of the members should have experience under the govt of India or state govt for 10 years	Similar to UPSC	Determined by Parliament	No qualifications prescribed.	Constitution Does not give any qualifications	Not mentioned in the constitution	Qualified to be appointed as a SC Judge (Attorney General) / High Court Judge (advocate general)
Tenure	65 years or 6 years whichever is earlier, determined by president.	65 or 6 years. (for both members and chairman)	62 or 6 years.	62 or 6 years.	Appointed once in 5 years	Determined by president of India. (it is normally for 3 years)	Nothing mentioned in Constitution	65 or 6 years	At the pleasure of president/ governor.
Removal	CEC – As like Judge of SC. Grounds: proved misbehavior or incapacity Others by President in consultation with CEC.	By President. Grounds: adjudged as insolvent, infirmity of mind or body, engages in employment outside office. SC inquiry is needed if removal is on grounds of misbehaviour	By President (although appointed by Governor) Grounds of removal are same as UPSC	Similar to UPSC	Temporary body	President	Nothing mentioned in Constitution	President on basis of Parliament resolution. Process is similar as a judge of Supreme court.	No procedures. In case of Attorney General power lies with President and for advocate general Governor has the power to make decisions.

KGS Campus, Patna - 6, Mob : 8877918018, 8757354880

Parameters	Election commission of India	UPSC	SPSC	JSPSC	Finance commission	National commission for SC/ST/BC	Special officer for linguistic minorities	CAG	Attorney/ Advocate general
Report submission	Not applicable	President	Governor	Governors of the states	President	President	President	President	Not applicable
Post retirement practice	No restrictions	Not eligible for employment outside UPSC, Member can be appointed as chairman of UPSC or SPSC. No provision for reappointment for UPSC chairman	Not eligible for re appointment or any other job under Govt. Member Can become chairman of the same or any other SPSC or UPSC Chairman or member. Chairman of SPSC can become Chairman of any other SPSC or member/chair- man of UPSC	Chairman can be appointed as member/ Chairman UPSC + Member JPSC can be appointed as Chairman of SPSC + 'Chair- man/member of UPSC	No restrictions	No limitations	Nothing mentioned in the constitution	Not eligible for any job under union or state govt.	Not debarred from private legal practice.
Other important facts	Functions include preparation of voter list + conducting elections for Parliament + State legislature + President + Vice President.			JSPSC is mentioned in article 315. Two or more states need to pass a resolution requesting for JPSC Parliament by law creates them (Simple majority required).		Quasi Judicial bodies + Advisory function + Hold powers of a 'civil court'. Evolution: Original constitution: Article 338 Provided special officer for SC/ST's. 65th amendment: replaced special officer with National commission for SC and ST. 89th amendment: Separated NCSC & ST into NCSC (Article 338) and NCST (338 A).		CAG – 1) Friend philosopher and guide to 'public account committee'. **2)** 'chief guardian' of public purse. **3)** Heads India audit and accounts department. **4)** Cannot participate in proceedings of Parliament.	**1)** Chief legal advisor -to the Government of India (GoI)/ Government of State. **2)** Prez. + Governor don't seek advise of these bodies. Governor takes advise from President. President from Supreme court. **3)** Enjoys all privilege + immunities of MP/MLA. **4)** Cannot advice against Government + cannot defend a criminal case. **5)** Can be a member of any legislative committee with no right to vote.

संवैधानिक निकाय

पैरामीटर	भारत निर्वाचन आयोग	यूपीएससी	एसपीएससी	जेएसपीएससी	वित्त आयोग	एससीबीसी /एसटी/ के लिए राष्ट्रीय आयोग	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	सीएजी	अटॉर्नीमहाधिवक्ता/
अनुच्छेद	324	315 – 323	315 – 323	315(हालांकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, यह एक वैधानिक निकाय है	280	338/338A/ 338B	350B (7 वां सीएए(	148 - 151	76/165
रचना	सीईसी अन्य चुनाव + आयुक्त राष्ट्रपति क्षेत्रीय + आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं	अध्यक्ष राष्ट्रपति + द्वारा निर्धारित अन्य सदस्य	सभापति + राज्यपाल द्वारा निर्धारित अन्य सदस्य	यूपीएससी के समान	अध्यक्ष +4 अन्य सदस्यों के समान	अध्यक्ष उपाध्यक्ष + +3 सदस्य	एकल सदस्य	एकल सदस्य	एकल सदस्य
नियुक्ति	राष्ट्रपति। ईसी का आकार भी निर्धारित करता है।	राष्ट्रपति	राज्यपाल	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	अपने हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा	राष्ट्रपति	अपने हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा	राष्ट्रपतिराज्यपाल/
योग्यता	निर्धारित नहीं है	आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत 10 साल का अनुभव होना चाहिए।	आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत 10 साल का अनुभव होना चाहिए	यूपीएससी के समान	संसद द्वारा निर्धारित	कोई योग्यता निर्धारित नहीं है।	संविधान में कोई योग्यता नहीं है	संविधान में नहीं है उल्लेख	एससी न्यायाधीश (अटॉर्नी जनरल)/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य महाधिवक्ता
कार्यकाल	65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।	65 या 6 साल। सदस्यों और अध्यक्ष दोनों के लिए	62 या 6 साल।	62 या 6 साल।	5 साल में एक बार होती है नियुक्ति	भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। यह आम तौर पर 3 साल के लिए होता है	संविधान में कुछ भी उल्लेख नहीं है	65 या 6 साल	राष्ट्रपतिराज्यपाल / की खुशी में।
हटाना	सीको सुप्रीम कोर्ट .सी .ई . केन्यायाधीश की तरह। आधारः दुर्व्यवहार या असमर्थता साबित सीईसी के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अन्य।	राष्ट्रपति द्वारा। आधारः दिवालिया घोषित, मन या शरीर की दुर्बलता, कार्यालय के बाहर रोजगार में संलग्न है। अगर दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया गया है तो SC जांच की जरूरत है	राष्ट्रपति द्वारा)although appointed by Governor) हटाने का आधार यूपीएससी के समान है	यूपीएससी के समान	अस्थायी निकाय	राष्ट्रपति	संविधान में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।	अध्यक्ष संसद के प्रस्ताव के आधार पर प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।	कोई प्रक्रिया नहीं है। महान्यायवादी के मामले में शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और महाधिवक्ता के लिए राज्यपाल के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

पैरामीटर	भारत निर्वाचन आयोग	यूपीएससी	एसपीएससी	जेएसपीएससी	वित्त आयोग	एससीबीसी के /एसटी/ लिएराष्ट्रीय आयोग	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	सीएजी	अटॉर्नीमहाधिवक्ता/
रिपोर्ट प्रस्तुत करना	लागू नहीं	राष्ट्रपति	राज्यपाल	राज्यों के राज्यपाल	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	लागू नहीं होते हैं
सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास	कोई पाबंदी नहीं	यू. पी. एस. सी. के बाहर रोजगार के लिए पात्र नहीं होने के कारण सदस्य को यू. पी. एस. सी. या एस. पी. एस. सी. का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यूपीएससी अध्यक्ष के लिए पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं	सरकार के तहत पुनः नियुक्ति या किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र नहीं। सदस्य उसी या किसी अन्य एसपीएससी या यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। एसपीएससी का अध्यक्ष किसी अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष या यूपीएससी का सदस्य/अध्यक्ष बन सकता है।	अध्यक्ष को यूपीएससी + के सदस्य/अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जे. पी. एस. सी. सदस्य को एस. पी. एस. सी. + का अध्यक्ष-पुरुष/यू. पी. एस. सी. का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।	कोई पाबंदी नहीं	कोई सीमा नहीं	संविधान में कुछ भी उल्लेख नहीं है	जो केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी नौकरी के लिए पात्र नहीं है।	निजी कानूनी अभ्यास से वर्जित नहीं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	कार्यों में संसद + राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति + उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराने वाली मतदाता सूची तैयार करना शामिल है।			जेएसपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों को जेपीएससी के लिए अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती हैसंसद कानून - द्वारा उन्हें बनाती है साधारण बहुमत की जरूरत		अर्ध न्यायिक निकाय + + सलाहकार कार्य 'सिविल कोर्ट' की शक्तियां रखते हैं। विकासः मूल संविधानः अनुच्छेद 338- एससी एसटी के/65 वें संशोधन के लिए विशेष अधिकारी प्रदान किया गयाः एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ विशेष अधिकारी को प्रतिस्थापित किया गया। 89वां संशोधनः एनसीएससी और एसटी को एनसीएससी अनुच्छेद)338) और एनसीएसटी में अलग किया गया)338 A).		सीएजी-1) मित्र दार्शनिक और 'सार्वजनिक लेखा समिति' के मार्गदर्शक। 2) सार्वजनिक पर्स का 'मुख्य संरक्षक'। 3) भारत लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख। 4. संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते।	1) भारत सरकार .जी) ओ . राज्य सरकार का मुख्य /(.एल कानूनी सलाहकार। 2) प्रेज़। निकायों राज्यपाल इन + से सलाह नहीं लेते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति। 3) सांसदविधायक के सभी / उन्मुक्ति का आनंद + विशेषाधिकार लेता है 4) सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकते आपराधिक मामले का + बचाव नहीं कर सकते। 5) किसी भी विधायी समिति का सदस्य हो सकता है जिसे वोट देने का कोई अधिकार नहीं है।

Non - Constitutional bodies								
Parameters	**NITI Aayog**	**NHRC**	**SHRC**	**CIC**	**SIC**	**CVC**	**NGT**	**Lokpal and Lokayukta**
Origin & Status	Executive order	Protection of Human rights act, 1993.Statutory	Protection of Human rights act, 1993. Statutory	RTI act, 2005. Statutory	RTI act, 2005. Statutory	CVC act, 2003. Statutory	NGT Act, 2010. Statutory	Lokpal and Lokayukta act, 2013. Statutory
Composition	PM (chairs) + Vice chairperson(PM elects) + Governing council(CM's + LG of UT's) + Regional councils + experts + Part time member (2)+ ex officio (4) + CEO	Total 5: 1 + 1 + 3 + 7 ex– officio members	Chairperson + 2 persons.	CIC (Chief Information commissioner) + 10 Information commissioner	SIC (State nformation commissioner) + 10 Information commissioner	1(Central vigilance) + 2 (Vigilance commissioner)	10 to 20 Judicial members + 10 to 20 Expert members	Chairperson + Maximum 8 member(50% judicial members) + Minimum 50% members shall be from SCs, STs, OBCs, Minorities and Woman.
Qualifications	Executive determines	Chairperson: CJI/ Judge SC. Other members: 1 member is serving or retired CJ –HC. 3 members should have knowledge or practical experience in human rights. Ex – officio members (National commission on – Minorities + SC + ST + BC + women + Protection of child rights + Chief commissioner for PwD's.	Chairperson: CJI – HC or Judge of HC. Members: Judge of HC (serving or retired) or District Judge (7 years' work experience + knowledge or experience related to Human Rights).	Person of eminence and knowledge + Cannot be appointed if - MP/MLA/Office of Profit	Person of eminence and knowledge + Cannot be appointed if - MP/MLA/Office of Profit		Chairperson – Either a serving or retired Judge of Supreme court or Chief Justice of High court. Appointed by GoI (based on recommendation of selection committee appointed by the Ministry of Environment and forests)	Chairperson: serving or retired Judge of Supreme court or CJ – High court. Members: Non Judicial members should have minimum 25 year experience in matters of anti – corruption, vigilance, finance etc.
Tenure and service conditions	Executive determines	70 years/ 3 years. Can be re – appointed. Salary etc. is determined by Central Govt.	70 years/3 year/ Reappointment – Yes. Salary etc. is determined by State Govt.	As prescribed by central government/ 65 years/ not eligible for reappointment	As prescribed by central government/ 65 years/ not eligible for reappointment	'4 year' or '65 years'/not eligible for reappointment	Different retirement age - Chairperson – 70 Judicial – 67 Non Judicial - 65 or 5 years	Both minimum (45 years) and maximum (70 years) age is prescribed. Tenure – 5 years. No reappointment.

Parameters	NITI Aayog	NHRC	SHRC	CIC	SIC	CVC	NGT	Lokpal and Lokayukta
Appointment	-	By President based on recommendation of a committee consisting of 6 members i.e. PM + Speaker (LS) + Deputy Chairman (RS) + Leader of opposition (LS & RS both) + Union Home minister.	By Governor based on recommendation of a committee consisting of (in case of bicameral legislature) CM + Speak-er (SLA) + Deputy Chair- man (SLC) + Leader of opposi-tion (SLA & SLC both) + State Home minister.	By 'President' on 'recommendation' of a committee Consisting of PM (Chairperson) + Union Cabinet Minister (Nominated by PM) + Leader of opposition in Lok Sabha	By Governor on recommendation of a committee consisting of CM (Chairperson) + State Cabinet Minister (Nominated by CM) + Leader of opposition in Legislative assembly.	'President' by warrant under his hand seal (on basis of recommendations of a selection committee). Composition: 1) Prime Minister + 2) Leader of Opposition (LS) + 3) Union Home Minister.	By Central Govt. (in consultation with CJI)	Lokpal members are appointed by President based on the recommen-dations of selection committee headed by PM consisting of Speaker – Lok Sabha + Leader of opposition – LS + CJI or SC Judge (nominated by CJI) + eminent Jurist recommended by other 4 members. Selection committee is assisted by search committee (to identify candidates). Lokayukta by Governor.
Removal	Executive determined	President can removed in the case of 1) insolvency 2) paid employment outside office 3) Infirmity of body and mind 4) unsound mind 5) convicted and sentenced to imprisonment 6) misbehaviour or incapacity (President has to refer the matter to the SC).	President can removed in the case of 1) insolvency 2) paid employment outside office 3) Infirmity of body and mind 4) unsound mind 5) convicted and sentenced to imprisonment 6) misbehaviour or incapacity (President has to refer to the matter of SC).	By President – Procedure is similar to NHRC.	By Governor – Procedure is similar to NHRC.	By President – Procedure is similar to NHRC	-	By President if insolvent, engages in paid employment and unfit due to infirmity of mind or body or guilty of misbehaviour (in this case petition signed by 100 MP's President sends it to SC for reference if SC recommends removal President passes an order.

Parameters	NITI Aayog	NHRC	SHRC	CIC	SIC	CVC	NGT	Lokpal and Lokayukta
Suo motu powers	-	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
Quasi – Judicial powers	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
Annual Report	-	Central Govt.	State Govt.	Central Govt.	State Govt.	Central Govt.	-	-
Other points	-	A) In case of violations by armed force – Can only seek report from Government of India B) Matters cannot be taken by NHRC – Service matters + Sub Judice + Anonymous + Frivolous + Over 1 year. C) Secretary General was provided by '2019' amendment – responsible for administrative + Financial powers.	A) Violation of human Right w.r.t subject in state + Concurrent list + UT's (If central Government confers it. B) Exception: UT of Delhi comes under National Human Rightscommission.			A) 'S.K Santhanam' committee recommendations B) Evolution – Initially 'Extra-legal' body later became a 'statutory body' (2003). C) Objective - Investigate into allegation of corruption against 'certain' officers (not all – scope of CVC is much narrow compared to Lokpal). D) CVC position = chairman of UPSC VC position = member of UPSC	A) HQ – Delhi Branches – Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai. B) Disposal of cases – Mandated to dispose cases within 6 months. C) Appeal against NGT Judgment – Supreme court D) Non - compliance with order of NGT – Fine (upto 10 crore) or 3 years jail. E) Governed – by principle of 'Natural Justice' (not bound by code of civil procedure or Indian evidence act).	A) PM + Ministers + MP's + Officer (Group A/B/C/D) + Officials of central Government + NGO's (who receive donations from foreign source in excess of 10 lakh). All authorities - Constitutional/Statutory extra-legal/ all authorities funded by Govt. come under its Jurisdiction. B) Immunities to PM: Jurisdiction of Lokpal 'does not' extend to Prime Minister w.r.t 5 fields – 1) Atomic Energ 2) Security 3) International Relations 4) Space 5) Public order. C) Superintendence over CBI + Power to give directions to CBI + Powers of civil court + Power of confiscation of material obtained via corruption + Recommend transfer/ suspension of a public servant etc.

Non - Constitutional bodies								
Parameters	**NITI Aayog**	**NHRC**	**SHRC**	**CIC**	**SIC**	**CVC**	**NGT**	**Lokpal and Lokayukta**
Origin & Status	Executive order	Protection of Human rights act, 1993.Statutory	Protection of Human rights act, 1993. Statutory	RTI act, 2005. Statutory	RTI act, 2005. Statutory	CVC act, 2003. Statutory	NGT Act, 2010. Statutory	Lokpal and Lokayukta act, 2013. Statutory
Composition	PM (chairs) + Vice chairperson(PM elects) + Governing council(CM's + LG of UT's) + Regional councils + experts + Part time member (2)+ ex officio (4) + CEO	Total 5: 1 + 1 + 3 + 7 ex– officio members	Chairperson + 2 persons.	CIC (Chief Information commissioner) + 10 Information commissioner	SIC (State nformation commissioner) + 10 Information commissioner	1(Central vigilance) + 2 (Vigilance commissioner)	10 to 20 Judicial members + 10 to 20 Expert members	Chairperson + Maximum 8 member(50% judicial members) + Minimum 50% members shall be from SCs, STs, OBCs, Minorities and Woman.
Qualifications	Executive determines	Chairperson: CJI/ Judge SC. Other members: 1 member is serving or retired CJ –HC. 3 members should have knowledge or practical experience in human rights. Ex – officio members (National commission on – Minorities + SC + ST + BC + women + Protection of child rights + Chief commissioner for PwD's.	Chairperson: CJI – HC or Judge of HC. Members: Judge of HC (serving or retired) or District Judge (7 years' work experience + knowledge or experience related to Human Rights).	Person of eminence and knowledge + Cannot be appointed if - MP/MLA/Office of Profit	Person of eminence and knowledge + Cannot be appointed if - MP/MLA/Office of Profit		Chairperson – Either a serving or retired Judge of Supreme court or Chief Justice of High court. Appointed by GoI (based on recommendation of selection committee appointed by the Ministry of Environment and forests)	Chairperson: serving or retired Judge of Supreme court or CJ – High court. Members: Non Judicial members should have minimum 25 year experience in matters of anti – corruption, vigilance, finance etc.
Tenure and service conditions	Executive determines	70 years/ 3 years. Can be re – appointed. Salary etc. is determined by Central Govt.	70 years/3 year/ Reappointment – Yes. Salary etc. is determined by State Govt.	As prescribed by central government/ 65 years/ not eligible for reappointment	As prescribed by central government/ 65 years/ not eligible for reappointment	'4 year' or '65 years'/not eligible for reappointment	Different retirement age - Chairperson – 70 Judicial – 67 Non Judicial - 65 or 5 years	Both minimum (45 years) and maximum (70 years) age is prescribed. Tenure – 5 years. No reappointment.

National commission for women:

- In sync with provisions of CEDAW-Convention on eliminations of all forms of discrimination against women.
- Status: Statutory + Quasi – Judicial Advisory body
- Appointment & Report: Government of India
- Composition: 1 + 5 + 1, Chaired by Women, Not an all women body, 1 SC/ST-Member
- Suo motu Power: Yes
- Function: Fund litigation, visit jail, remand home etc.

National commission on Minorites

- Look into concerns and issues of Religious minorities.
- Status: Statutory Quasi-Judicial + advisory body.
- Appointment: By Government of India
- Chairman: 1+1+5-Chairman + Vice chairman + Members. Not an all minority body.

National commission on Protection of Child Rights (NCPCR)

- It fulfils India's commitment under UNCRC- United Nation convention on Rights of child.
- Appointment: By Government of India
- Membership: 1+1+6-Chairman + Vice chairman + Members
- Recently, status was given to NCPCR as an ex officio member in NHRC
- Commission works under Ministry of Women and Child Development

Central Bureau of Investigation

- Not a statutory body.
- Established by executive resolution of union home ministry.
- Derives powers from Delhi special police establishment act, 1946 • Director of CBI is appointed by committee consisting of PM + leader of opposition in LS + Chief Justice of India.
- Tenure of Director-2 years.
- GoI can appoint officers above rank of SP on recommendations of committee headed by CVC, Vigilance commissioners, secretary of home and Personnel.

गैर संवैधानिक निकाय

पैरामीटर	नीति आयोग	एनएचआरसी	एसएचआरसी	सीआईसी	एसआईसी	सीवीसी	एनजीटी	लोकपाल और लोकायुक्त
उत्पत्ति और स्थिति	कार्यकारी आदेश	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	मानव अधिकारों का सांविधिक संरक्षण अधिनियम, 1993	सांविधिक आरटीआई अधिनियम, 2005	सांविधिक आरटीआई अधिनियम, 2005	सांविधिक सीवीसी अधिनियम, 2003	सांविधिक एनजीटी अधिनियम, 2010	सांविधिक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 वैधानिक
रचना	PM (chairs) उपाध्यक्ष)PM elects) शासी परिषद सीएम के) + (यूटी के एलजी क्षेत्रीय परिषदों के + विशेषज्ञ अंशकालिक सदस्य)2) + पदेन)4) CEO	कुल 5:1+1 + 3+7 पदेन सदस्य	अध्यक्ष 2 व्यक्ति।	सीआईसी मुख्य) + (सूचना आयुक्त 10 सूचना आयुक्त	एसआईसी राज्य) + (सूचना आयुक्त 10 सूचना आयुक्त	1 (केंद्रीय सतर्कता (2 सतर्कता आयुक्त	10 से 20 न्यायिक सदस्य +10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य	अध्यक्ष अधिकतम 8 सदस्य)50% न्यायिक सदस्य (न्यूनतम50% सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला से होंगे।
योग्यताएं	कार्यपालक निर्धारित करता है	अध्यक्षः सी .जे; आईया .सी .एच-. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सदस्यः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवारत या) या (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश)7 वर्ष का कार्य अनुभव + मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान या (अनुभव	श्रेष्ठता और ज्ञान का व्यक्ति यदि- /विधायक/सांसद लाभ का कार्यालय नियुक्त नहीं किया जा सकता है	श्रेष्ठता और ज्ञान का व्यक्ति यदि- /विधायक/सांसद लाभ का कार्यालय नियुक्त नहीं किया जा सकता है			श्रेष्ठता और ज्ञान का व्यक्ति यदि- /विधायक/सांसद -लाभ का पद सर्वोच्च -अध्यक्ष के न्यायालय सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त चयन समिति की सिफारिश के आधार पर गोल द्वारा नियुक्त	अध्यक्षः उच्चतम न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश- उच्च न्यायालय वारत या के से सेवानिवृत्त न्यायाधीश। -सदस्यः गैर न्यायिक सदस्यों को भ्रष्टाचार विरोधी, सतर्कता, वित्त आदि के मामलों में न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

पैरामीटर	नीति आयोग	एनएचआरसी	एसएचआरसी	सीआईसी	एसआईसी	सीवीसी	एनजीटी	लोकपाल और लोकायुक्त
नियुक्ति	-	6 सदस्यों वाली समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री + लोकसभा अध्यक्ष (लोकसभा) उपसभापति + (राज्यसभा) विपक्ष के नेता लोकसभा और) (राज्यसभा दोनों +केंद्रीय गृह मंत्री।	राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर द्विसदनीय) विधायिका के सीएम (मामले में स्पीकर + (एसएलए) उपाध्यक्ष विपक्ष (एसएलसी)) के नेताSLA & SLC both) राज्य के गृह मंत्री।	प्रधानमंत्री + (अध्यक्ष) केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्)री द्वारा नामित (लोकसभा + में विपक्ष के नेता से बनी समिति की 'सिफारिश' पर राष्ट्रपति द्वारा	राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री (अध्यक्ष) राज्य कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा) + (नामित विधानसभा में विपक्ष के नेता से बनी समिति की सिफारिश पर।	सिफारिशों के आधार पर अपने हाथ की मुहर के तहत वारंट द्वारा 'राष्ट्रपति'। एक चयन समिति। संरचनाः 1) प्रधानमंत्री + 2) विपक्ष के नेता (एलएस) +3) केंद्रीय गृह मंत्री।	केंद्र सरकार द्वारा।)in consultation with CJI)	लोकपाल सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें अध्यक्ष-नेता विपक्ष के + लोकसभा-सीजेएल या एससी + एलएस (सीजेआई द्वारा नामित) न्यायाधीश अन्य4 सदस्यों द्वारा अनुशंसित प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। चयन समिति को उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए खोज समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त।
कार्यकाल और सेवा की शर्तें	कार्यकारी	70 वर्ष/3 वर्ष निर्धारित करता है। फिर से नियुक्त किया जा सकता है। वेतन आदि। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।	70 वर्ष/3 वर्ष-पुनर्नियुक्ति/ हाँ। वेतन आदि। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।	केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित/65 वर्ष/पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र	केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित/65 वर्षपुनर्नियुक्ति के / लिए पात्र नहीं	4 वर्ष "या"65 वर्ष पुनर्नियुक्ति /" के लिएपात्र नहीं	अलगअलग - सेवानिवृत्ति की -उम्र अध्यक्ष70 न्यायिक-67 गैर-न्यायिक-65 या 5 वर्ष	न्यूनतम)45 वर्ष और अधिकतम ( )70 वर्षआयु दोनों निर्धारित हैं। (-कार्यकाल5 वर्ष। कोई पुनर्नियुक्ति नहीं।

पैरामीटर	नीति आयोग	एनएचआरसी	एसएचआरसी	सीआईसी	एसआईसी	सीवीसी	एनजीटी	लोकपाल और लोकायुक्त
हटाना	कार्यपालक ने तय किया	राष्ट्रपति को 1) दिवाला 2) संबंध के बाहर भुगतान रोजगार 3) शरीर और मन की कमजोरी के मामले में हटाया जा सकता है। 4) अस्वस्थ मन 5) दोषी ठहराया गया और कारावास की सजा सुनाई गई 6) दुर्व्यवहार या अक्षमता)President has to refer the matter to the SC)	राष्ट्रपति को 1) दिवाला 2) संबंध के बाहर भुगतान रोजगार 3) शरीर और मन की कमजोरी के मामले में हटाया जा सकता है। 4) अस्वस्थ मन 5) दोषी ठहराया गया और कारावास की सजा सुनाई गई 6) दुर्व्यवहार या अक्षमता)President has to refer the matter to the SC)	राष्ट्रपति द्वारा- प्रक्रिया एनएचआरसी मान हैके स	राज्यपाल द्वारा- प्रक्रिया एनएचआरसी के समान है।	राष्ट्रपति द्वारा- प्रक्रिया एनएचआरसी के समान है	-	राष्ट्रपति द्वाराप्रक्रिया एनएचआरसी के - राष्ट्रपति द्वारा यदि -समान है दिवालिया होजाता है, भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न होता है और मन या शरीर की कमजोरी के कारण अयोग्य होता है या दुर्व्यवहार का दोषी होता है इस मामले में)100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (अगर सुप्रीम कोर्ट हटाने की सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति इसे संदर्भ के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं राष्ट्रपति एक आदेश पारित करते हैं।
सुओ मोटो शक्तियाँ	-	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
अर्धन्यायिक - शक्तियाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
वार्षिक रिपोर्ट	-	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	-	-

पैरामीटर	नीति आयोग	एनएचआरसी	एसएचआरसी	सीआईसी	एसआईसी	सीवीसी	एनजीटी	लोकपाल और लोकायुक्त
अन्य बिंदु	-	एसशस्त्र बल (द्वारा उल्लंघन के केवल -मामले में भारत सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं बीमामले (-एनएचआरसी + सेवा मामलों + उप न्याय बेनामी तुच्छ द्वारा नहीं लिए जा सकते हैं1 वर्ष से अधिक। गमहासचिव (" को2019 संशोधन- + प्रशासनिक वितीय शक्तियों के लिए द्वारा "जिम्मेदार प्रदान किया गया था।	एराज्य (+ समवर्ती सूची UT में मानव अधिकार w.rt विषय का उल्लंघन यदि) केंद्र सरकार इसे है। प्रदान करती बी(अपवादः केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आता है।			ए (S.K संथानम समिति की सिफारिशें बी शुरू में-विकास ('अतिरिक्तकानूनी - निकाय' बाद में एक 'वैधानिक निकाय' बन गया)2003). सी (उद्देश्य-'कुछ' अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना सीवीसी का सारा दायरा लोकपाल की तुलना में बहुत कम है। डीसीवीसी की (= स्थिति यूपीएससी के अध्यक्ष, वीसी की स्थिति यूपीएससी के सदस्य	एदिल्ली -मुख्यालय (भोपाल-शाखाएं, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। बीमामलों का (-निपटान6 महीने के भीतर मामलों का निपटान करने के लिए अनिवार्य। सीएनजीटी के फैसले (-के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय डी जुर्माना-एनजीटी ( )10 करोड़ तक या (3 साल की जेल के आदेश का पालन न करना। ई ('प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांत द्वारा शासित है जो सिविल प्रक्रिया संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा बाध्य नहीं है	ए + सांसद + मंत्री + पीएम (केंद्र + (डी/सी/बी/समूह ए) अधिकारी सरकार के गैर सरकारी संगठनों के अधिकारी जो विदेशी स्रोतों से10 लाख से अधिक दान प्राप्त करते हैं। सभी प्राधिकरणवैध/संवैधानिक-ानिक अतिरिक्तवित्त सरकार द्वारा/कानूनी- पोषित सभी प्राधिकरण। इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बीपीएम को उन्मुक्तिः लोकपाल का (अधिकार क्षेत्र'नहीं' प्रधानमंत्री w.rt 5 क्षेत्रों तक विस्तारित है-1) परमाणु ऊर्जा 2) सुरक्षा 3) अंतर्राष्ट्रीय संबंध 4. स्पेस 5) सार्वजनिक व्यवस्था। सी + र अधीक्षणसीबीआई प (+ सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति दीवानी अदालत की शक्तियाँ भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त सामग्री को जब्त करने की शक्ति लोक सेवक आदि के निलंबन की सिफारिश /स्थानांतरण करना।

राष्ट्रीय महिला आयोगः

- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर CEDAW-कन्वेंशन के प्रावधानों के साथ तालमेल में।
- स्थितिः सांविधिक न्यायिक सलाहकार निकाय-अर्ध +
- नियुक्ति और रिपोर्टः भारत सरकार
- संरचनाः 1 + 5 + 1, महिलाओं की अध्यक्षता में, सभी महिला निकाय नहीं, 1 एससीसदस्य-टीएस/
- सुओ मोटो पावरः हाँ
- कार्यः फंड मुकदमेबाजी, जेल का दौरा, रिमांड होम आदि।

अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रीय आयोग

- धार्मिक अल्पसंख्यकों की चिंताओं और मुद्दों को देखें।
- स्थितिः सांविधिक अर्धसलाहकार निकाय। + न्यायिक-
- नियुक्तिः भारत सरकार द्वारा
- अध्यक्षः 1+1 + 5-अध्यक्ष सदस्य। एक पूर्ण अल्पसंख्यक निकाय न + उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

- यह बाल अधिकारों पर यूएनसीआरसीसंयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है।-
- नियुक्तिः भारत सरकार द्वारा
- सदस्यताः 1+1 + 6-अध्यक्ष सदस्य + उपाध्यक्ष +
- हाल ही में, एनसीपीसीआर को एनएचआरसी में पदेन सदस्य का दर्जा दिया गया • महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आयोग कार्य करता है

केंद्रीय जांच ब्यूरो

- एक वैधानिक निकाय नहीं।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से शक्तियां प्राप्त करता है सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है जिसमें पीएम + लोकसभा में विपक्ष के नेता + भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- निदेशक का कार्यकाल-2 वर्ष।
- सीवीसी, सतर्कता आयुक्तों, गृह सचिव और कार्मिक सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर गोल एसपी के रैंक से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।